



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 अप्रैल, 1984/30 चैत्र, 1906

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, अप्रैल 11, 1984

संख्या 1-21/84 वि० स०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 11)

जो दिनांक 11 अप्रैल 1984 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा पुर-स्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचना के राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

विश्वेश्वर वर्मा,
सचिव।

1984 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धन राशि के भुगतान को अधिकृत करने और उनके विनियोग करने हेतु—

विधेयक।

भारतीय गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1984 कहलाएगा।

संक्षिप्त नाम

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां जिनका जोड़ हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1984 की अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियों को मिलाकर पांच अरब, सतासो करोड़, इकानवे लाख, अठाईस हजार, पांच सौ रुपये है निकाली जाये और उनका वित्तीय वर्ष 1984-85 की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभारों के भुगतान हेतु उपयोग किया जाए।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वर्ष 1984-85 के लिए 5,87,91,28,500 रुपये की राशि निकालना।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन धन राशियों को निकालने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धन राशियों का विनियोग धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

विनियोग।

अनुसूची

(देखिए धाराएं 2 और 3)

मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनाधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		₹0	₹0	₹0
1	विधान सभा तथा निर्वचन राजस्व	1,72,55,000	1,70,000	1,74,25,000
2	राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् राजस्व	37,54,000	15,16,500	52,70,500
3	न्याय प्रशासन राजस्व	1,53,74,000	43,51,000	1,97,25,000
4	सामान्य प्रशासन राजस्व	8,65,69,000	15,10,000	8,80,79,000
	पूँजी	50,000	—	50,000
5	भू-राजस्व राजस्व	5,71,94,000	—	5,71,94,000
	पूँजी	8,75,000	—	8,75,000
6	आबकारी तथा कराधान राजस्व	1,79,31,000	—	1,79,31,000
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा राजस्व	13,24,57,000	—	13,24,57,000
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पूँजी	60,83,95,000	—	60,83,95,000
	पूँजी	1,18,96,000	—	1,18,96,000
9	चिकित्सा और परिवार नियोजन राजस्व	20,62,24,000	—	20,62,24,000
	पूँजी	2,77,81,000	—	2,77,81,000
10	लोक निर्माण राजस्व	35,14,23,000	—	35,14,23,000
	पूँजी	2,00,10,000	—	2,00,10,000
11	कृषि राजस्व	19,61,03,000	—	19,61,03,000
	पूँजी	8,15,95,000	—	8,15,95,000
12	लघु सिंचाई राजस्व	10,89,70,000	—	10,89,70,000
	पूँजी	2,31,08,000	—	2,31,08,000
13	भूमि तथा जल संरक्षण राजस्व	6,33,29,000	—	6,33,29,000
	पूँजी	48,00,000	—	48,00,000
14	पशुपालन तथा दुग्ध विकास राजस्व	5,97,45,000	—	5,97,45,000
	पूँजी	70,50,000	—	70,50,000
15	मत्स्य राजस्व	55,43,000	—	55,43,000
	पूँजी	15,95,000	—	15,95,000
16	वन राजस्व	15,98,09,000	—	15,98,09,000
	पूँजी	1,70,00,000	—	1,70,00,000
17	सड़कें तथा पुल राजस्व	9,73,00,000	—	9,73,00,000
	पूँजी	26,88,02,000	—	26,88,02,000
18	सप्लाई, उद्योग तथा खनिज राजस्व	9,52,38,000	—	9,52,38,000
	पूँजी	2,33,00,000	—	2,33,00,000
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जलें राजस्व	7,74,22,000	—	7,74,22,000
	पूँजी	72,20,000	—	72,20,000

1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	राजस्व 34,52,32,000 पूँजी 9,66,00,000	—	34,52,32,000 9,66,00,000
21	सामुदायिक विकास	राजस्व 13,90,16,000 पूँजी 1,80,000	—	13,90,16,000 1,80,000
22	सहकारिता	राजस्व 2,97,40,000 पूँजी 1,74,55,000	—	2,97,40,000 1,74,55,000
23	खाद्य एवं पोषाहार	राजस्व 3,59,01,000 पूँजी 8,65,70,000	—	3,59,01,000 8,65,70,000
24	जल तथा विद्युत विकास	राजस्व 1,47,00,000 पूँजी 29,36,50,000	—	1,47,00,000 29,36,50,000
25	सिंचाई, नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	राजस्व 1,24,29,000 पूँजी 1,77,71,000	—	1,24,29,000 1,77,71,000
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	राजस्व 1,62,42,000 पूँजी 30,00,000	—	1,62,42,000 30,00,000
27	सड़क परिवहन	राजस्व 28,71,000 पूँजी 2,24,91,000	—	28,71,000 2,24,91,000
28	पर्यटन	राजस्व 51,41,000 पूँजी 1,24,25,000	—	51,41,000 1,24,25,000
29	श्रम तथा रोज़गार	राजस्व 1,62,30,000 पूँजी 13,60,000	—	1,62,30,000 13,60,000
30	आवास	राजस्व 64,11,000 पूँजी 1,86,89,000	—	64,11,000 1,86,89,000
31	नगर विकास	राजस्व 3,80,55,000 पूँजी 65,00,000	—	3,80,55,000 65,00,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवायें	राजस्व 10,60,95,000 पूँजी 19,52,000	—	10,60,95,000 19,52,000
33	वित्त	राजस्व 9,81,20,000 पूँजी —	26,35,43,000 96,75,00,000	36,16,63,000 96,75,00,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूँजी 2,28,00,000	—	2,28,00,000
35	जन जातीय विकास	राजस्व 22,21,95,000 पूँजी 9,56,00,000	—	22,21,95,000 9,56,00,000
	कुल जोड़	4,64,05,38,000	1,23,85,90,500	5,87,91,28,500

उद्देश्य तथा कारणों का कथन

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय, पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) के अनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
अप्रैल 11, 1984.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-ए-सी (1) 26/83]

राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1984 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को, विधान सभा में पुरःस्थापित करने तथा उस पर सभा द्वारा विचार किये जाने का अभिस्ताव किया है।

[Authorised English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Sankhya 2) Vidhaik, 1984, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Bill No. 11 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1984.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of the financial year 1984-85.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 1984.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate, inclusive of sums specified in column (3) of the Schedule to the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1984 to the sum of five hundred eighty-seven crore, ninety-one lakh, twenty-eight thousand and five hundred rupees, towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1984-85 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of sum of Rs. 5,87,91,28,500 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1984-85.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of this Act.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Demand	Services and Purposes		Voted by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections	Revenue	1,72,55,000	1,70,000	1,74,25,000
2	Governor and Council of Ministers	Revenue	37,54,000	15,16,500	52,70,500
3	Administration of Justice	Revenue	1,53,74,000	43,51,000	1,97,25,000
4	General Administration	Revenue	8,65,69,000	15,10,000	8,80,79,000
		Capital	50,000	—	50,000
5	Land Revenue	Revenue	5,71,94,000	—	5,71,94,000
		Capital	8,75,000	—	8,75,000
6	Excise and Taxation	Revenue	1,79,31,000	—	1,79,31,000
7	Police and Fire Protection	Revenue	13,24,57,000	—	13,24,57,000
8	Education, Art and Cultural Affairs and Scientific Research	Revenue	60,83,95,000	—	60,83,95,000
		Capital	1,18,96,000	—	1,18,96,000
9	Medical and Family Planning	Revenue	20,62,24,000	—	20,62,24,000
		Capital	2,77,81,000	—	2,77,81,000
10	Public Works	Revenue	35,14,23,000	—	35,14,23,000
		Capital	2,00,10,000	—	2,00,10,000
11	Agriculture	Revenue	19,61,03,000	—	19,61,03,000
		Capital	8,15,95,000	—	8,15,95,000
12	Minor Irrigation	Revenue	10,89,70,000	—	10,89,70,000
		Capital	2,31,08,000	—	2,31,08,000
13	Soil and Water Conservation	Revenue	6,33,29,000	—	6,33,29,000
		Capital	48,00,000	—	48,00,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	Revenue	5,97,45,000	—	5,97,45,000
		Capital	70,50,000	—	70,50,000
15	Fisheries	Revenue	55,43,000	—	55,43,000
		Capital	15,95,000	—	15,95,000
16	Forest	Revenue	15,98,09,000	—	15,98,09,000
		Capital	1,70,00,000	—	1,70,00,000
17	Roads and Bridges	Revenue	9,73,00,000	—	9,73,00,000
		Capital	26,88,02,000	—	26,88,02,000
18	Supplies, Industries and Minerals	Revenue	9,52,38,000	—	9,52,38,000
		Capital	2,33,00,000	—	2,33,00,000
19	Social Security, Welfare and Jails	Revenue	7,74,22,000	—	7,74,22,000
		Capital	72,20,000	—	72,20,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply	Revenue	34,52,32,000	—	34,52,32,000
		Capital	9,66,00,000	—	9,66,00,000
21	Community Development	Revenue	13,90,16,000	—	13,90,16,000
		Capital	1,80,000	—	1,80,000
22	Co-operation	Revenue	2,97,40,000	—	2,97,40,000
		Capital	1,74,55,000	—	1,74,55,000

1	2	3		
No. of Demand	Services and Purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
23	Food and Nutrition	Revenue 3,59,01,000	—	3,59,01,000
		Capital 8,65,70,000	—	8,65,70,000
24	Water and Power	Revenue 1,47,00,000	—	1,47,00,000
	Development	Capital 29,36,50,000	—	29,36,50,000
25	Irrigation, Navigation,	Revenue 1,24,29,000	—	1,24,29,000
	Drainage and Flood Control	Capital 1,77,71,000	—	1,77,71,000
26	Stationery and Printing	Revenue 1,62,42,000	—	1,62,42,000
		Capital 30,00,000	—	30,00,000
27	Road Transport	Revenue 28,71,000	—	28,71,000
		Capital 2,24,91,000	—	2,24,91,000
28	Tourism	Revenue 51,41,000	—	51,41,000
		Capital 1,24,25,000	—	1,24,25,000
29	Labour and Employment	Revenue 1,62,30,000	—	1,62,30,000
		Capital 13,60,000	—	13,60,000
30	Housing	Revenue 64,11,000	—	64,11,000
		Capital 1,86,89,000	—	1,86,89,000
31	Urban Development	Revenue 3,80,55,000	—	3,80,55,000
		Capital 65,00,000	—	65,00,000
32	Other Administrative Services	Revenue 10,60,95,000	—	10,60,95,000
		Capital 19,52,000	—	19,52,000
33	Finance	Revenue 9,81,20,000	26,35,43,000	36,16,63,000
		Capital —	96,75,00,000	96,75,00,000
34	Loans to Government Servants	Capital 2,28,00,000	—	2,28,00,000
35	Tribal Development	Revenue 22,21,95,000	—	22,21,95,000
		Capital 9,56,00,000	—	9,56,00,000
Grand Total		4,64,05,38,000	1,23,85,90,500	5,87,91,28,500

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 of the Constitution of India, to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1984-85.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The 11th April, 1984.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(1) 26/83]

The Governor, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1984 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by, the Legislative Assembly of the said Bill.